



मतलबी लोग आपके साथ नहीं बिल्कुल आपकी हैसियत के साथ होते हैं।  
स्वामी विवेकानन्द



# माही की गूज

बेबाकी के साथ... सच

Www.mahikigunj.in, Email-mahikigunj@gmail.com

वर्ष-04, अंक - 15 (साप्ताहिक)

खगासा, गुरुवार 13 जनवरी 2022

पृष्ठ-8, गूल्य-5 रुपए

## ग्राम पंचायतों का वित्तीय अधिकार किसको...?

माही की गूज, झाड़ुआ।

नि-स्तरीय पंचायत चुनाव एक बार पिछे टलने के बाद सभी के मान में अब एक ही स्तरलाई है कि, अब किसे मिलेगा वित्तीय अधिकार...? कोरोना की पहली लहर के बाद स्तरीय कानून बनाकर वित्तीय अधिकार दे दिए गए थे, किंतु पिछले दिनों ग्राम पंचायत के चुनावों की घोषणा के बाद सही आचार सहिता लागू हो गई थी और प्रधान के भी सारे अधिकार समाप्त हो गए थे। लेकिन पिछला वर्ष के गलत आचारण के चलते सरकार को एक बार पिछे चुनाव रद्द करना पड़े। जिसके पिछले दिनों ग्राम पंचायतों के अधिकार आचार सहिता लागू होने के साथ ही समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आगामी चुनाव मह में चुनाव होना सभी नहीं लग रहा है। ऐसे में कई ग्राम पंचायतों को कारोंगों के पैसे अटके पड़े हैं, कई मन्दिरों की मजदूरी बढ़की है। ऐसे में उनका पैसा जब तक चुनाव ना हो जाए अटका ही रहेगा क्या...? यही नहीं कई दुकानदारों व करेकरों के पैसे भी कई ग्राम पंचायतों में अटके पड़े हैं उनको भुगतान करोगा...? यही नहीं कई ग्रामों में कई विकास कार्य अप्रूव भी हो रहे हैं। ऐसे के अभाव में कैसे पौर्ण होंगे...? कागिस पुराने सरपंचों की मांग जुनूनी है, ऐसे में सरकार को शीघ्र नियन्त्रण लेना चाहिए कि, अधिकार ग्राम पंचायतों के वित्तीय अधिकार किसको देना चाहती है...? क्योंकि विलंब की स्थिति में नुकसान ग्राम वासियों के साथ ही अंततः सरकार को ही उठाना पड़े सकता है।

## राष्ट्रपति से मांगी सीएम के पिता ने इच्छामृत्यु

हुर्गी। अपने बयानों से अक्सर चर्चा में रहने वाले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से इच्छा मृत्यु की मांग की है। उन्होंने राष्ट्रीय मतदाता जागति मंच के माध्यम से राष्ट्रपति को पत्र भेजा है। जिसमें नंदकुमार बघेल की मांग है कि, इंवाएं के बजाए पूरे देश में बैलों परेप से चुनाव कराया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उन्हें राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को इच्छामृत्यु प्रदान करने की अनुमति दी जाए।

### यह बाराई वर्जन

नंदकुमार बघेल ने अपने पत्र में लिखा कि, आपको अत्यन्त दुर्घ के साथ अवगत करना पड़ रहा है कि देश के नागरिकों के समस्त संवैधानिक अधिकारों का व्यापक कराया जाए और अन्य अधिकारों के बदले लोकतंत्र के तीनों स्तरभूति विधियों, न्यायपालिका और कार्यपालिका धर्मता होती जा रही है। मीडिया भी लोकतंत्र के तीनों स्तरभूतों के इशारे पर कार्य कर रही है। देश के नागरिकों के अधिकारों के उपयोग में लाने से पूर्व मान्यता प्राप्त

संबंध में कोई सुनने वाला नहीं है? जिन जनप्रतिनिधियों को मतदाता अपनी ही समस्या के लिए चुनते हैं। उनकी आवाज भी निरन्तर दर्ती जा रही है। विधायिका देश के समस्त सरकारी विभागों व उपकरणों को अपने चेहरों को बेच रही है। कार्यपालिका भ्रष्टाचार में सालिम होकर अपने आवाजी सन्तानों के लिए अधिक से अधिक धन इकड़ा कर उनका भविष्य सुरक्षित करने में लागी है।

### ईटीएम पर उठाए सवाल

नंदकुमार बघेल ने अपने पत्र में लिखा कि, लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार मतदान के अधिकार के सम्बन्धीय अधिकारों का व्यापक कराया जाए और संवैधानिक अधिकार का हनिया जा रहा है। ईटीएम मरीजों को द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय मानवान्मारण प्राप्त संस्था या सरकार ने 100 प्रतिशत शुद्धाता से काम करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया है? किसी भी मरीजों को उपयोग में लाने से पूर्व मान्यता प्राप्त

ईटीएम के स्थान पर मतपत्र एवं पेटी से मतदाता संभव नहीं? तो मुझे 25 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर इच्छा मृत्यु करने की अनुमति प्रदान करने की बूझ करें। नंदकुमार बघेल जागृति मंच नाम की संस्था चलाती है।

तकनीक संस्था या सरकार द्वारा मरीजों का शुद्धाता से काम करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। पिछे भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भरत में ईटीएम मरीजों से मतदान कराकर ग्रे वोट के ऊपर संवैधानिक अधिकार का हनिया जा रहा है। ईटीएम मरीजों से मतदान कराकर सरकारें देश की सरकारी धराया 153(ए) और 505, एक के तहत एक्साइंट्री दर्ज कर किया गया था। इसके अलावा भी उनके कई बयानों से विवाद होता रहा है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंदकुमार बघेल कई विवादों से चर्चा में रहे हैं। 86 वर्ष के नंदकुमार बघेल स्वतंत्र रूप से मतदाता जागृति मंच नाम की संस्था चलाते हैं। ब्राह्मण समाज के खिलाफिटियों करने पर धार्याएं जो ढोड़ीनगर थाने में आईपीसी की धराया 153(ए) और 505, एक के तहत एक्साइंट्री दर्ज कर किया गया था। इसके अलावा भी उनके कई बयानों से विवाद होता रहा है।

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। प्रदेश में पहले पंचायतों के संचालन की जिम्मेदारी सरपंच और सचिवों को दी गई थी, बाद में शिवाजी सरकार के खिलाफलामबंद होते नजर आ रहे हैं और उन्हें उनके वित्तीय अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए

पंचायत चुनाव निरस्त होने के बाद से गहमगहमी बढ़ी है। रोजाना कोई नया आदेश, कोई नया दाव देखने की मिल रही है। पंचायतों के संचालन को लेकर आगल असमजेस की स्थिति बड़ी हूँ है। इसका विवाद अधिकार वापस ले लिया और सरपंच सचिवों को दिए गए









## गूँज ब्रीफ

जिले में सामने आया पहला ओमिक्रोन का मामला

माही की गूँज, मंदसौर। जिले में ओमिक्रोन का पहला केस सामने आया है, इसकी उछि हो चुकी है। 25 दिसंबर को जिले में विदेश से एक महिला पॉजिटिव पाई गई थी। यह महिला दुर्घट से मंदसौर आई थी। जिसके बाद महिला का सैपल जीनाम सीक्रेट्स के लिए दिल्ली लैब में भेजा गया था। रिपोर्ट में ओमिक्रोन की पुष्टि हुई है। कलेक्टर ने इसकी जानकारी देते हुए यह बताया कि, विदेश से आए एक पॉजिटिव को सैपल जीनाम सीक्रेट्स के लिए दिल्ली भेजा गया था। जिसकी रिपोर्ट भी आगई है। उसमें से एक महिला में ओमिक्रोन की पुष्टि हुई है। सबसे अच्छी बात यह है कि, महिला अब स्वस्थ होकर आइसोलेशन से दिस्चार्ज हो चुकी है। डीएम के अनुसार जीनाम सीक्रेट्स के लिए 5 सैपल और भी भेजे गए हैं। उन्हें भी बताया कि, सभी मरीजों पर बारबार ध्वनि दें रहे हैं। राहत की बात यह है कि, जिले में कई भी कांविटिव पॉजिटिव स्थित में नहीं हैं। मंदसौर में ओमिक्रोन केस का यह पहला मामला है।

## इस मुक्त भारत चुनौतियां एवं समाधान विषय पर

## प्रतियोगिताएं हुई आयोजित

माही की गूँज, खरगोन। शायकीय महाविद्यालय खरगोन की शायकीय सेना योजना इकाई एवं डेंगू बिन क्लब के संयुक्त तत्वाधान में प्राचार्य डॉ. डीडी महाजन एवं जिला संग्राहक नोडल अधिकारी डॉ. सुरेश अवासे के मार्गदर्शन में युवाओं के मध्य इस मुक्त भारत चुनौतियां एवं समाधान विषय पर प्रसन्न मंच और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। प्रसन्न मंच प्रतियोगिता में साकारन धन्दन प्रथम, प्रथम बड़ी विजेता और कृतिका यादव ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इन प्रतियोगिताओं को जिला चिकित्सालय से नान फुरस्कार राशि प्रदान की जाएगी। प्रतियोगिता में भागीरथ खतवासे, सागर नैरव, खुशी यादव, चौमणी गुप्ता, मणि भालेकर, सुविजा पटेलार, चौमणी ग्रामणी, जयपाल सलकी, प्रज्ञाली पटेलार, प्रियंका यादव सहित अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया।

## स्वास्थ्य शिविर में 13 बच्चों को सर्जरी के लिए किया विन्हाकित

माही की गूँज, खरगोन। शायकीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत जिला चिकित्सालय के डीडीआईसी भवन में कठे हों, परे तालू का निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जन्म से लेकर 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को विभिन्न ग्रामों से स्थिति एवं शिविर में लाया गया। शिविर बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए मानवनक्षत्र राशि दीडीआईसी प्रबंधक विनोद पंडव ने जानकारी देते हुए बताया कि, जन्मजात विनियोगों से ग्रसित इन बच्चों को निःशुल्क सर्जरी लाहोटी अस्पताल भोपाल में होती है। शिविर में कठे होंट, एस तालू से ग्रसित कुल 19 बच्चों का पंजीयन हुआ। जिनमें से लाहोटी अस्पताल के चिकित्सक डॉ. चंचल ठारू द्वारा 13 बच्चों को सर्जरी के लिए विन्हाकित किया गया। चिकित्सक अपने साथ भी भोपाल सर्जरी के लिए जाएं तथा सर्जरी उपरान्त पुगे खरगोन भेजा जाएं।

## कोविड-19 के बचाव के लिए अस्थाई नियुक्ति

माही की गूँज, खरगोन। कोरोना के लगातार बढ़ते संक्रमण के अवश्यक रोकथाम के लिए गत वर्ष विभिन्न पर्यावरण की अस्थाई नियुक्ति की गई थी। इस वर्ष भी ऐसी ही परिस्थितियां निर्मित होने से पूर्व अवश्यक मानव संसाधन की पूर्ति के लिए कलेक्टर श्रीमती अनुग्रहा पी ने सायंकार्य पर सीपीएचओ डॉ. डीएस चौहान को आवश्यक अमलों की जानकारी देते हुए दिए हैं। इसी क्रम में सीएमएचओ डॉ. चौहान ने जिले विजया कि, कोविड-19 के अंतर्गत पूर्णतः अस्थाई मानव संसाधन की आवश्यकता है। इसके लिए जिले के प्रधानमंत्री ने अपने एक टेक्नीशियन और एक एनेसेसिस्ट, एक अंटीटोक्सिन एवं एक एनेसेसिस्ट नियुक्त किया गया। अंतर्गत कुल 49 पद अस्थाई तौर पर भरे रहे हैं। 15 जनवरी को शीर्ष सीपीएचओ कार्यालय में 15 जनवरी की बाकि सक्षात्कार के माध्यम से भर्ती होगी।

## माही की गूँज, आबुआ(अलीराजपुर)

कस्बे की विभिन्न समस्याओं में से एक प्रमुख समस्या स्वास्थ्य से जुड़ी है, यह है प्रदूषण। यह मानव स्वास्थ्य पर किस तह प्रदूषण तालियां हैं यह यहां के निवासियों से बेहतर कौन जन सकता है। बार-बार शिक्षियों के बाबजूद प्रश्नपत्र का मौन रहना इन्हें समर्थन देने जैसा है। समाचार पत्रों में समाचारों तथा प्रकारों के प्रतिनिधियों द्वारा जिलाधिकारी से मिलकर समस्या से अवगत करने के बाबजूद एक बर्बं में भी उचित निदान नहीं निकाला जाता है।

इस व्यवसाय की प्रक्रम शर्त यही बताई जा रही है कि, इनके भड़े आवासीय क्षेत्रों से दूर होना चाहिए। इन्हें पकाने हेतु जो भी ईंधन उत्योग में लाया जाए उसका धुआ तथा धूल एवं राख के कागज नहीं करें, पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुँचाए, मगर इसका पालन नहीं किया जारहा है। ईंटों को पकाने हेतु पथर कायले का उत्योग किया जा रहा है। जिसका धुआ जब

निकलता है तो उस से बदू आती है जिस कारण आखों में जलन, अस्थमा अद्यरा आ जाता है हवा का रुख यदि लक्ष्मी गामड़ से भी मुलाकात कर रवाई का अनुरोध किया जाए। सबह सड़क मार्ग की ओर होता तथा शाम को धुएं के कारण कर्बों में चलाने में परेशानी होती है।

जिस कारण आखों में जलन, अस्थमा अद्यरा आ जाता है हवा का रुख यदि लक्ष्मी गामड़ से भी मुलाकात कर रवाई का अनुरोध किया जाए। उनका कारण वर्ष अधिकारी श्रीमती निलालू को परेशानी द्वारा जारी होती है। इस समस्या की जानकारी देने हेतु आबुआ पत्रकार संघ के समस्यों ने विवात वर्ष अनुविधानीय अधिकारी श्रीमती निलालू को परेशानी द्वारा जारी होती है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है।

ये ईंट भड़े किसी के पेट पर लात नहीं मार सकते आवासीय क्षेत्र के साथ-साथ शिक्षण संस्थाओं को भी प्रभावित कर रहे हैं। आबुआ में स्थित ईंट भड़ों के पास जब भी काई जाता है तो वह वर्बं पुराने एक पत्र मोबाइल से दिखाते हैं कि, इन्हें इस धंधे की छूट है। पत्र में कुछांतों के धम्बिंक स्थल भी भौजूद हैं जहां अनेजान वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती है। इस समस्या की जानकारी देने हेतु आबुआ पत्रकार संघ के समस्यों ने विवात वर्ष अनुविधानीय अधिकारी श्रीमती निलालू को बरतन तथा कवेतू आदि के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर्षान में उन्हें ईंट बन कर तैयार है तथा भड़े लाग और धारणा प्राप्त होती है, जिससे अति शीघ्र लोगों को प्रदूषण का समाना करना पड़ता है। और प्रश्नपत्र का आड के लिए है। इसी पत्र की आड में यह लाग बड़े तर्क पालों की संभाला में ईंट बनाना पकाना आदि के बाद बड़े स्तर व्यवसाय करते हैं। वर



# दिया तले अंधेरा: राजस्व सीमा क्षेत्र में सड़क निर्माण, ठेकेदार की मौज

**बिना अनुमति चल रहा अवैध उत्थनन का कार्य, सूचना अधिकार से मिली जानकारी में हुआ खुलासा**

माही की गूँज, पेटलावद। राकेश गेहूला

विभाग ने अपनी ओर से दी गई जानकारी में बताया कि, निर्माण एजेंटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति र । ज स्व कार्यालय में नहीं दी गई न ही को इन शासन द्वारा दिया गया है, और शासन द्वारा निर्धारित सर्वे नम्बर से करेगा या माल उठाएगा इसके लिए नियमनुसार राजस्व विभाग से अनुमति लेनी होती है, जिसकी आवेदन अनुविधानीय अधिकारी या तहसीलदार को करना होता है। आवेदन के बाद क्षेत्र के हल्का पटवारी अपना जाच प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, जिसके आधार पर सरकारी या निजी सर्वे नम्बर से उत्थनन की अनुमति दी जाती है और शासन द्वारा इसके पुरात विभाग द्वारा प्रौद्योगिक विधिवत करना होता है। लेकिन क्षेत्र में काम करने वाले ठेकेदार ऐसा कछु नहीं करते जिसकी जानकारी के लिए कुछेके रोड निर्माण के लिए ठेकेदार द्वारा उत्थनन संबंधी अनुमति देने की जानकारी सूचना अधिकारी अधिकारीय के माध्यम से ली और जो जबाब मिला तो बहेही चोकाने वाला सामने आया।

आरटीआई में हुआ खुलासा किसी ठेकेदार ने उत्थनन के लिए राजस्व विभाग में कार्ड आवेदन तक नहीं दिया

मामले की जानकारी के लिए जब इस संबंध में राजस्व कार्यालय में आरटीआई के माध्यम से पछ्या गया कि, ग्राम परवान वर्ष करवावर और गोपलालपुर से धोधड तक बाजाए जा रहे अग्रिकल्पना रोड निर्माण है, तो नियमान्य एजेंटी द्वारा किन शासकीय सर्वे नम्बरों से मोरम खनन होते हैं और अनुमति दी गई, उन सर्वे नम्बरों की जानकारी एजेंटी द्वारा प्रस्तुत आवेदन, पटवारी प्रतिवेदन और अनुमति की प्राप्तियां प्रति चाहीं गई। लेकिन जो जबाब आरटीआई के जबाब में आया वो बहेही चोकाने वाला था। राजस्व

विभाग ने अपनी ओर से दी गई जानकारी में बताया कि, निर्माण एजेंटी द्वारा किसी भी प्रकार की अनुमति र । ज स्व कार्यालय में नहीं दी गई न ही को

प्रकरण या जांच नहीं की गई। पूरे मामले में सबसे बड़ी कठोरी निर्माण क्षेत्र का हल्का पटवारी होता है, जिसकी जानकारी में पूरा कार्य ठेकेदार करता है और शासकीय परेशनी से बचने के लिए पटवारी भी भेट पूजा कर अपना कार्य कर लेता है और शिकायत अखार की खबरों के बाद वही ठेकेदार पटवारी के माध्यम से राजस्व अधिकारीय से भी साठ-गांठ कर लेता है। चूकी ये ठेकेदार बड़े शहरों से आते हैं और अपने राजनीतिक स्वरूप और किसी बड़े नेता का नाम अपने कर मामला वही स्पष्ट दफ्तर करते हैं।

राजस्व विभाग की भूमिका संदेहास्पद, पटवारी के माध्यम से ठेकेदार जमा लेते हैं सेटिंग

वैसे तो शासकीय सर्वे नम्बर से किसी भी प्रकार का उत्थनन बिना अनुमति के करना अपराध है, जिसके लिए शासन ने भारी जुर्माना और वाहन राजस्व तक नियमान्य एजेंटी द्वारा किन शासकीय सर्वे नम्बरों से मोरम खनन होते हैं बड़े ठेकेदार निर्माण के साथ ही रॉयली जमा होने के नाम पर मनचाहे शासकीय नम्बर से उत्थनन कर लेते हैं। पूरे मामले में राजस्व विभाग की भूमिका संदेहास्पद नजर आ रही है जिसका मामला संज्ञान में आने के बाद भी कोई



- गोपलपुर-धोधड मार्ग पर ठेकेदार द्वारा बैकडो डम्फर मोरम विभाग राजस्व की अनुमति के खंडन कर डाल दिया, यही साल करडावद से करडावद मार्ग पर भी है।

प्रकरण या जांच नहीं की गई। पूरे मामले में सबसे बड़ी भूमिका पर सबल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन बड़े रसूखदार, रोड टेकेदारों द्वारा किए जा रहे बिना अनुमति उत्थनन पर लगाम लगाए गए।

जो कहीं न कहीं राजस्व और हल्का पटवारीयों की भूमिका पर सबल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन बड़े रसूखदार, रोड टेकेदारों द्वारा किए जा रहे बिना अनुमति उत्थनन पर लगाम लगाए गए।

जो कहीं न कहीं राजस्व और हल्का पटवारीयों की भूमिका पर सबल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में इन बड़े रसूखदार, रोड टेकेदारों द्वारा किए जा रहे बिना अनुमति उत्थनन पर लगाम लगाए गए।

बामिनिया-रायपुरिया मार्ग पर साइट भराव के कार्य की अब तक नहीं ली सूधा, कार्वाई का आशासन

गूँज के पिछले अंक में बामिनिया से रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने कार्वाई का आशासन दिया था। लेकिन अब तक कोई जांच के आदेश सामने नहीं आए।

कहने को तो अवैध उत्थनन कार्यों पर कार्वाई के लिए पूरा-पूरा खानिंज विभाग अलग से बना रहा है और लेकिन किसी भी कार्य के पहले खानिंज विभाग के अधिकारीयों तक उनकी भेट पूजा की राशि पहुँच जाती है, जिसके बाद वे इन कार्यों की तपश्चरण तक नहीं करते।

रोड निर्माण में भारी मामला में लाने वाली गिर्धी सलाहूंद के लिए ये ठेकेदार स्थानीय नियमान्य के बालाकर अलगाव के लिए एक विभाग की भूमिका को लेकिन विभाग के माध्यम से बनाया जाए। इनका अधिकारी ने एसडीएम को आवेदन देते हुए बताया कि, घर के पास रहने वाले विजयसिंह राठौर, हेमतसिंह राठौर के द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग का कार्य किया जाता है और उनके घर में ब्लास्टिंग के टोटे रखे हुए हैं। ये ठेकेदार और उनकी सहायता करने वाले अधिकारीयों पर उचित कार्वाई हो सके।

कहने को तो अवैध उत्थनन कार्यों पर कार्वाई के लिए पूरा-पूरा खानिंज विभाग अलग से बना रहा है और लेकिन किसी भी कार्य के पहले खानिंज विभाग के अधिकारीयों तक उनकी भेट पूजा की राशि पहुँच जाती है, जिसके बाद वे इन कार्यों की तपश्चरण तक नहीं करते।

रोड निर्माण में भारी मामला में लाने वाली गिर्धी सलाहूंद के लिए ये ठेकेदार स्थानीय नियमान्य के बालाकर अलगाव के लिए एक विभाग की भूमिका को लेकिन विभाग के माध्यम से बनाया जाए। इनका अधिकारी ने एसडीएम को आवेदन देते हुए बताया कि, घर के पास रहने वाले विजयसिंह राठौर, हेमतसिंह राठौर के द्वारा अवैध रूप से ब्लास्टिंग का कार्य किया जाता है और उनके घर में ब्लास्टिंग के टोटे रखे हुए हैं। ये ठेकेदार और उनकी सहायता करने वाले अधिकारीयों पर उचित कार्वाई हो सके।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुलासा किया था, जिसके बाद राजस्व विभाग की ओर से तहसीलदार जगदीश वर्मा ने इसे इन बड़े ठेकेदारों के संबंध में भी पूछ लिया।

पेटलावद विभाग एक अंक में बामिनिया के रायपुरिया मार्ग पर चल रहे साइट भराव के कार्य में अवैध रूप से उत्थनों में लाए जा रहे मोरम का खुल